गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 321
दि. 25.03.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बनाम राज्य की टकराहट, ईडी की याचिका पर उठे संवैधानिक सवाल, अप्रैल तक टली अहम सुनवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की शीर्ष न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस समय एक अहम संवैधानिक बहस देखने को मिली, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच अधिकारों की सीमा को लेकर तीखा टकराव सामने आया। यह मामला केवल एक जांच एजेंसी की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन, संघीय ढांचे और संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या जैसे गंभीर मुद्दों को भी केंद्र में ला खड़ा किया। अदालत ने फिलहाल इस मामले में कोई अंतिम निर्णय दिए बिना सुनवाई को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन जिस तरह की तीखी बहस और सवाल-जवाब इस दौरान सामने आए, उससे यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यह मामला देश की संवैधानिक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।

इस पूरे विवाद की जड़ में वह घटना है, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार संगठन आई-पैक के दफ्तर में तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने कथित तौर पर जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और एजेंसी के काम में बाधा डाली। ईडी ने इसे कानून के शासन पर सीधा हमला बताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की मांग की।

मामले की सुनवाई जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने की, जहां शुरुआत से ही बहस का रुख केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों की गहराई तक पहुंच गया। अदालत ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया कि क्या कोई केंद्रीय एजेंसी या उसके अधिकारी सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यह सवाल इसलिए अहम था क्योंकि अनुच्छेद 32 मूलतः नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, न कि सरकारी संस्थाओं को।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने जोरदार दलील दी कि ईडी की यह याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था कि ईडी एक वैधानिक संस्था है, न कि कोई 'व्यक्ति' या 'नागरिक', इसलिए वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया गया, तो यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक मिसाल साबित हो सकती है, क्योंकि इससे केंद्र की एजेंसियों को राज्यों के खिलाफ सीधे सर्वोच्च अदालत में जाने का रास्ता मिल जाएगा, जो राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और ईडी की ओर से पेश पक्ष ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह केवल एक एजेंसी का मामला नहीं है, बल्कि कानून के शासन और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का सवाल है। उनका कहना था कि यदि किसी जांच एजेंसी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाता है, तो यह पूरे न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कई तीखे और जटिल सवाल भी उठाए, जिन्होंने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया। अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि यदि किसी छापेमारी के दौरान राज्य का सर्वोच्च पद संभालने वाला व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, तो ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी क्या कदम उठा सकते हैं। क्या वे राज्य पुलिस के पास जा सकते हैं, या फिर उनके पास कोई अन्य कानूनी विकल्प होता है? इन सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामला केवल अधिकार क्षेत्र का नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशासनिक जटिलताओं का भी है।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने से बचना चाहती है। चूंकि मामला ऐसे समय सामने आया है जब राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, इसलिए यह सवाल भी उठा कि क्या इस याचिका का समय चुनावी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि यदि कोई गंभीर संवैधानिक मुद्दा सामने आता है, तो केवल समय के आधार पर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि देश के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जहां एक ओर केंद्र की एजेंसियां अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, वहीं राज्य सरकारें अपनी स्वायत्तता और अधिकार क्षेत्र की रक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रही हैं। इस टकराव ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या मौजूदा कानूनी ढांचा ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है या इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई को अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई में इस मामले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर और गहराई से विचार किया जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे की सुनवाई में अदालत इस जटिल विवाद को किस दिशा में ले जाती है और क्या कोई ऐसा फैसला सामने आता है, जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सके।

इस पूरे प्रकरण ने यह भी दिखा दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब भी यह संतुलन डगमगाता है, तो उसकी गूंज सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचती है, जहां से न केवल एक मामले का समाधान निकलता है, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन भी तय होता है।

13 साल की पीड़ा के बाद मिली मुक्ति: हरीश राणा ने तोड़ी जिंदगी से लंबी जंग, इच्छामृत्यु पर फिर गहरा हुआ देशव्यापी विमर्श

(जीएनएस)। गाजियाबाद। जीवन और मृत्यु के बीच 13 वर्षों तक चली एक असाधारण और दर्दनाक जंग का मंगलवार को अंत हो गया, जब गाजियाबाद के हरीश राणा ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अंतिम सांस ली। हरीश लंबे समय से कोमा की स्थिति में थे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद चिकित्सा प्रक्रिया के तहत उनका जीवन धीरे-धीरे समाप्त हुआ। यह मामला केवल एक व्यक्ति की पीड़ा की कहानी नहीं, बल्कि देश में इच्छामृत्यु, मानवीय गरिमा और कानूनी-नैतिक सीमाओं पर गहन बहस को एक बार फिर केंद्र में ले आया है।

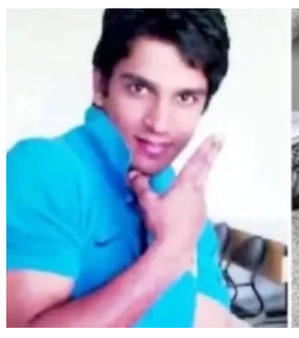

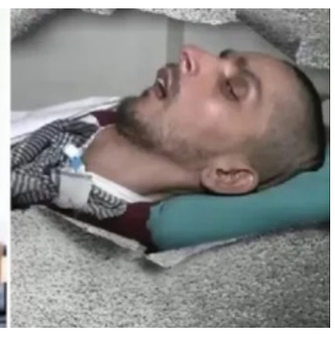

हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे। वे एम्स के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (आईआरसीएच) के उपशामक देखभाल वार्ड में भर्ती थे, जहां एक विशेष मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए थी। पिछले एक सप्ताह से उन्हें भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा था, जो इच्छामृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया का हिस्सा था। डॉक्टरों के अनुसार, यह एक अत्यंत संवेदनशील और नियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसमें मरीज को कृत्रिम जीवन समर्थन से धीरे-धीरे मुक्त किया जाता है। अंततः छह दिनों की इस प्रक्रिया के बाद उनका निधन हो गया। इस दौरान अस्पताल का माहौल बेहद भावुक और पीड़ादायक बना रहा। हरीश के माता-पिता लगातार उनके पास मौजूद रहे। उनकी मां अस्पताल के गलियारे में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करती रहीं, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद अब भी बाकी हो। बेटे की सांसें चलती देख एक मां का दिल टूट रहा था, लेकिन वह असहाय भी थी। उन्होंने भावुक होकर कहा था कि "मेरा बेटा अभी सांस ले रहा है, उसकी धड़कन चल रही है, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा रहा है।" यह दृश्य केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति का दर्द था, जिसने इस पूरे मामले को करीब से देखा।

हरीश राणा की यह कहानी साल 2013 से शुरू होती है, जब वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। रक्षाबंधन के दिन, अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए वह पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। यह हादसा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। गंभीर रूप से घायल हरीश को पहले पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। बाद में उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया से ग्रसित बताया।

क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति के हाथ-पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं और वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। हरीश के साथ भी यही हुआ। वह न बोल सकते थे, न चल सकते थे और न ही किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि कर सकते थे। उनका जीवन पूरी तरह बिस्तर तक सीमित हो गया था। समय के साथ उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका दर्द लगातार बढ़ता गया। बेटे की इस असहनीय स्थिति को देखते हुए उनके माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इच्छामृत्यु की अपील की, लेकिन 8 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल हरीश के परिवार के लिए एक राहत लेकर आया, बल्कि इसने देश में इच्छामृत्यु के अधिकार को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है, खासकर तब जब वह असहनीय पीड़ा में हो और उसके ठीक होने की कोई संभावना न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने चिकित्सा, कानून और समाज के बीच उस जटिल संबंध को उजागर किया है, जहां जीवन को बचाने की कोशिश और पीड़ा से मुक्ति दिलाने की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना बेहद कठिन हो जाता है। एक ओर जहां डॉक्टरों का कर्तव्य जीवन को बचाना होता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, जहां जीवन केवल एक लंबी पीड़ा बनकर रह जाता है।

हरीश राणा का निधन केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल की याद दिलाता है, जिसका जवाब समाज और कानून दोनों को मिलकर खोजना होगा—क्या हर स्थिति में जीवन को बनाए रखना ही सही है, या कभी-कभी सम्मानजनक मृत्यु भी एक मानवीय विकल्प हो सकती है? यह प्रश्न आने वाले समय में भी बहस का विषय बना रहेगा।

ओडिशा में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, 55 लाख का इनामी सुकुरु साथियों संग मुख्यधारा में लौटा

(जीएनएस)। भुवनेश्वर। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जारी अभियान में ओडिशा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कुख्यात माओवादी सुकुरु ने मंगलवार को कंधमाल जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ चार अन्य माओवादियों ने भी हथियार डालकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। इस सामूहिक सरेंडर को राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

आत्मसमर्पण की आधिकारिक पुष्टि करते हुए ओडिशा पुलिस के एंटी-नक्सल ऑपरेशन के एडीजी संजीब पांडा ने बताया कि सुकुरु लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था और उसकी तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। कंधमाल और आसपास के जंगलों में वह माओवादी गतिविधियों का सक्रिय सदस्य रहा है और संगठन में उसकी भूमिका काफी अहम मानी जाती थी। उसके सरेंडर से न केवल संगठन को बड़ा झटका लगा है, बल्कि इलाके में सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुकुरु पर करीब 55 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जो उसकी सक्रियता और संगठन में उसकी हैसियत को दर्शाता है। वह कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा है और सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। ऐसे में उसका आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि लगातार दबाव और सटीक रणनीति के जरिए नक्सल नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि सुकुरु और उसके साथियों के इस फैसले के पीछे केवल सुरक्षा बलों का दबाव ही नहीं, बल्कि सरकार की पुनर्वास नीति भी एक बड़ा कारण रही है। राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास, रोजगार और समाज में पुनर्स्थापना की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्होंने कई माओवादी सदस्यों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। यही वजह है कि बीते कुछ समय में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी ठोस प्रयास जरूरी होते हैं। जिन इलाकों में लंबे समय से विकास की कमी रही है, वहां के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। सरकार की नई नीतियां इसी दिशा में काम कर रही हैं, जिसका असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है।

सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में और भी माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लगातार चल रहे ऑपरेशनों, खुफिया सूचनाओं के बेहतर इस्तेमाल और स्थानीय स्तर पर बढ़ते विश्वास के कारण माओवादी संगठन कमजोर पड़ रहा है। कई इलाकों में उनकी पकड़ ढीली होती नजर आ रही है, जिससे उनके सदस्यों के बीच असंतोष भी बढ़ रहा है।

हालांकि, अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभी यह लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियां अब भी सक्रिय हैं और उन्हें खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन सुकुरु जैसे बड़े नेता का आत्मसमर्पण निश्चित रूप से इस संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

"द यश मंगलम शो" की नई लघु फिल्म "युवा बिहार" में युवा पीढ़ी के जज्बे और जुनून की असरदार अभिव्यक्ति

"बिहार दिवस" पर पटना में हुआ शानदार लोकार्पण

(जीएनएस)। मुंबई। भारत के ऐतिहासिक प्रदेश बिहार के स्थापना दिवस की वर्षगाँठ के अवसर पर इंटरनेट के लोकप्रिय माध्यम यू-ट्यूब पर एक सुरुचिपूर्ण लघु फिल्म "युवा बिहार का लोकार्पण हुआ, जिसमें बिहार की युवा पीढ़ी के अद्भुत हुनर एवं बुलंद हौसलों के साथ युवाओं के जोश, जज़्बे और जुनून की असरदार अभिव्यक्ति की गई है। पिछले दिनों जारी विभिन्न लघु फिल्मों को मिली निरंतर सफलता के बाद सृजनात्मक उत्कृष्टता के एक सशक्त ब्रांड के रूप में लोकप्रिय होते जा रहे "द यश मंगलम शो" की नवीनतम कड़ी के रूप में इस लघु फिल्म " युवा बिहार" का लोकार्पण बिहार दिवस के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के टेन्डर हार्ट्स इंटरनेशनल, स्कूल में किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने भी इस जोशीली लघु फिल्म का अवलोकन कर इसकी सृजनात्मक उत्कृष्टता को सराहा है। एक अनूठी सृजनात्मक पहल के अंतर्गत "वाइब्रेन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई" द्वारा "महतपुरकर एंड मंगलम फाउंडेशन" के बैनर तले नवसृजित यह अद्भुत लघु फिल्म "युवा बिहार" सोशल मीडिया के सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब पर मौजूद सुरुचिपूर्ण चैनल "द यश मंगलम शो' के अंतर्गत अपलोड की गई है, जो अपने अनूठे कंटेंट और प्रस्तुतीकरण के विलक्षण अंदाज़ के लिए काफी लोकप्रिय है और व्यापक तौर पर सराहा जाता रहा है। इससे पहले इस लोकप्रिय शो की "धरोहरः ए पोएटिक सागा", *"शिल्पकार", "योगा रिट्रीट", "सेहत के रखवाले", *कारगिल विजय दिवस- ए पोएटिक सागा, "मैं भारत हूँ..!", *"पथ प्रदर्शक"* " द लीगेसी ऑफ मैथेमेटिक्स" और "वंदे मातरम" जैसी प्रभावशाली कड़ियाँ यू-ट्यूब पर काफी अच्छा प्रतिसाद पा चुकी हैं। इस शो के जोशीले और युवा शो-बॉय यश मंगलम हैं, जो सिर्फ़ 16 वर्ष की आयु में ही अपनी दमदार आवाज़, आकर्षक व्यक्तित्व और सशक्त प्रस्तुतीकरण से अपनी शानदार शैली की बदौलत शो- बिज़ की दुनिया में अपने पैर बखूबी जमा रहे हैं। इस विशेष लघु फिल्म का प्रभावशाली लेखन मुंबई के सुपरिचित गीतकार, मंच संचालक तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने किया है, जिसमें बिहार राज्य के गौरवशाली इतिहास और इसके राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पहलुओं को बखूबी पिरोया गया है। उल्लेखनीय है कि गजानन महतपुरकर द्वारा लिखी गई 12 से अधिक लघु फिल्में पहले ही यू-ट्यूब पर धूम मचा चुकी हैं। इसी क्रम में अब नवीनतम लघु फिल्म के ज़रिये गजानन महतपुरकर की सशक्त लेखनी और सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुपम मंगलम के कुशल निर्देशन का कमाल यू-ट्यूब पर लोकप्रिय हो रहा है। इस सशक्त, प्रभावशाली और संवेदनशील लघु फिल्म को अपने कुशल निर्देशन के ज़रिये पर्दे पर उतारने का दायित्व बखूबी निभाया है, मुंबई के विज्ञापन एवं फिल्म जगत के भरोसेमंद निर्देशक अनुपम मंगलम ने, जिनको पिछले 25 सालों में 300 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में बनाने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वरिष्ठ राजनेता श्री राजाराम पांडेय जी की संकल्पना पर आधारित इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री जय कपूर हैं। इसके एसोसिएट प्रोड्यूसर श्री राजीव भार्गव और क्रिएटिव डायरेक्टर सुश्री रत्ना नीलम पांडे हैं। इस नवसृजित लघु फिल्म का भावपूर्ण पार्श्व संगीत समीर पखाले ने दिया है। वीडियोग्राफी संजय वैष्णव, वी एफ एक्स संयोजन गिनीलाल सालुंके, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कला मंगलम और एडिटिंग प्रताप शिंदे द्वारा सुनिश्चित की गई है। पोस्ट प्रोडक्शन "वाइब्रेशन्स मीडिया वर्क्स, मुंबई" ने किया है। बिहार दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर जारी इस विशेष लघु फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और इसकी विलक्षण गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। इस ऊर्जावान लघु फिल्म का प्रदर्शन म्यूज़ियम, बिहार के अनेक विद्यालयों और पटना के विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। इस लघु फिल्म की प्रमुख पंक्तियाँ कुछ इस तरह रची गई हैं :- सच बताइये दोस्तों ! क्या बिहार सिर्फ एक जगह का नाम है ? या फ़िर एक सोच की शैली या एक अनूठी शक्ति का भंडार जिसे है सही वक़्त का इन्तज़ार..! ये राज्यसिर्फ ज़मीन नहीं है, ये मेमोरी है...! ये मूवमेंट है...! ये समय के कैनवास पर जाँबाज़ इरादों का स्टेटमेंट है..! जो कभी रुकता नहीं ! कभी थकता नहीं...! कभी झुकता नहीं..! दोस्तों, अपना बिहार सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं, बल्कि इंडियन फ्यूचर के नैक्स्ट चैप्टर का टाइटल है..... बिहार...! भारतीय संस्कृति के धरातल पर है बुलंद हौसलों की हुंकार..! ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं.... चिंगारी है, आज हर टेलेंट की पूरी तैयारी है, ये युवा बिहार है मित्रों अब हमारी बारी है..!

यह लघु फिल्म इस यू-ट्यूब लिंक पर देखी जा सकती है :-
https://youtu.be/Ec2e9-rnX80?si=t_h-ZvdfYEHBs7qE

संपादकीय

जानलेवा पेयजल

यह शर्मनाक है कि जिस शहर को पिछले सात सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया जा रहा था, वहां पेयजल में सीवर का पानी मिल जाने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाए। बताया जाता है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर के पानी के रिसाव से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। घटनाक्रम के बाद सौ के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सैकड़ों लोग दूषित पेयजल के उपयोग से बीमार हैं। वैसे भी किसी सभ्य समाज में व्यक्ति आत्मग्लानि से यह सुनकर बीमार हो जाएगा कि जिस पानी को उसने उपयोग किया, उसमें सीवर का गंदा पानी मिला था। निस्संदेह, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ही है, जिसके चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। नगर निगम ही नहीं, इस महकमे से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, इंदौर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल करता रहा है तो इस दुर्घटना ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना दिया। इस दुखद स्थिति के चलते मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विडंबना यह है कि नागरिकों ने पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जवाबदेह अधिकारी तब हरकत में आए, जब कई लोगों की जान जा चुकी थी। यहां तक कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का महकमा आता है, उनकी संवेदनहीन बयानबाजी ने लोगों का आक्रोश बढ़ाया है। हालांकि, तल्ख आलोचना के बाद मंत्री ने खेद जताया है। यहां तक कि इस घटना के बाद मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी दोषियों से प्रायश्चित करने व दंड देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ छोटे स्तर के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण से इन मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों का प्रायश्चित हो पाएगा?

लेकिन विडंबना है कि यह समस्या केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे-बड़े शहरों में गाहे-बगाहे दूषित जल आपूर्ति के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन, मुआवजे की घोषणा और कनिष्ठ अधिकारियों का निलंबन मामले में लीपापोती का उपक्रम बन चुका है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण' के मंत्र पर जोर दिया था। तब उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जीवनयापन को सुगम बनाने के लिये प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। सवाल है कि जब नागरिकों को स्वच्छ हवा और जल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाएगा तो जीवनयापन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? मध्य प्रदेश की दोहरे इंजन वाली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी बड़ी योजना व नारा तब तक अर्थहीन है जब तक उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का समर्थन प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद-21 के तरह जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की त्रासदी दर्शाती है कि शहरी बुनियादी ढांचे के खराब रखरखाव के कारण इस अधिकार का उल्लंघन कितनी आसानी से हो सकता है। निष्कर्ष यह भी है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और शासन संबंधी नारे व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। इंदौर की घटना के बाद देश के सभी राज्यों में संबंधित विभागों व स्थानीय निकायों को पेयजल से जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा कि कहीं पेयजल आपूर्ति लाइन जर्जर होकर दूषित पानी से तो नहीं मिल रही है। पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप लाइनों का नियमित रूप से अवलोकन होना चाहिए। इस बाबत मंत्रालय और निकाय के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में लापरवाही के दोषियों को सख्त सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह मामला गैर इरादतन हत्या जैसा भी तो है।

संतुलन के लिए जरूरी रणनीतिक दिशा तय करना

> "वैश्विक ताकतों के बीच दुनियाभर के संसाधनों को कब्जाने की होड़ लगी है। खासकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति यकीनी बनाने के लिए। रूस-यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिका-इस्राइल और ईरान की जंग - विश्व की आर्थिकी को बड़ी हानि हो रही है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और आंतरिक-बाह्य सुरक्षा के लिए रणनीतिक दिशा तय करनी होगी।

जून, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज़ फर्डिनेंड की हत्या उन मुख्य घटनाओं में से एक मानी जाती है जिनके परिणाम में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अंतर्निहित बड़ा कारण था कि 'केंद्रीय शक्तियां' (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और ओटोमन साम्राज्य) दुनियाभर में साम्राज्यवादी विस्तार और औपनिवेशीकरण करने की दौड़ में देर से शामिल हुईं, जिसमें ब्रिटेन व फ्रांस वर्चस्व कायम कर चुके थे।

कैसर विल्हेम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मनी ने साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा पाली थी, और इसी के चलते तनाव-संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। बाकी सब इतिहास है। चार साल (1914-18) चले युद्ध में सैन्य व नागरिक हताहतों की संख्या 1.5 से 2.2 करोड़ होने का अनुमान है। वर्साय संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो पाया। लेकिन दुखद, इंसान की स्मृति इतनी कमज़ोर कि शायद ही कोई साल गुज़रता हो जब विश्व में कहं न कहीं हिंसा न भड़कती हो।

व्यक्तियों की तरह, गरीब देश भी आपस में नहीं लड़ते-सिवाय कुछ मामलों के जहां विकास अभी कबीलाई चरण में है। अमीर, विकसित और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश ही परस्पर लड़ते हैं, या फिर गरीब लेकिन प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राष्ट्रों को उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म व नस्ल की इसमें अहम भूमिका हैं-अमूमन छद्म रूप में। किसी इंसान या देश को आखिर कितनी ज़मीन चाहिए? क्या यह कभी काफी रही? या फिर यह कि आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, लालसी उतनी ही बढ़ती जाती है?

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी, जापान और इटली ('धुरी की शक्तियां') अपने विशाल संसाधन के बूते धीरे-धीरे शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे; लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत द्वीपों और एशिया को जीतने का प्रयास किया। शक्तिशाली देशों को सदा प्रगति की ज़रूरत रहती है; यथास्थिति कभी पर्याप्त नहीं रही। उन्हें और भूमि व संसाधन चाहिए होते हैं, लूटने के लिए और धन व गुलाम बनाने को और अधिक स्त्री-पुरुष चाहिए होते हैं। इसी कारण द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया, जिसमें करोड़ों जानें गई और शहर और देश तबाह हुए। द्वितीयविश्व युद्ध में हुआ नुकसान प्रथम विश्वयुद्ध के मुकाबले कहीं अधिक था।

आज दौड़ दुर्लभ भू-खनिजों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और इनके खनन, प्रसंस्करण से चुंबक बनाने की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुरक्षित करने की लगी है। अमेरिका और चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाओं को इनकी ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अपने बड़े-बड़े डेटा सेंटर चलाने के लिए बेतहाशा ऊर्जा चाहिये। चूंकि हर चीज़ को जीडीपी वृद्धि के रूप में आंका जाता है, इसलिए कंपनियों के लिए ग्रोथ ज़रूरी है और मुकाबला बहुत कड़ा, गलाकाट है। निजी उद्योग से शुरू हुआ यह मामला धीरे-धीरे सियासी अखाड़े में फैल जाता है और जल्द ही सेनाएं भी आकर शामिल हो जाती हैं।

'कटिंग ऑफ द चाईनीज़ मेलन' (चीन को कब्जाने की तत्कालीन औपनिवेशिक ताकतों में होड़) से लेकर 'स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका' (अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाने की दौड़) तक, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब बड़ी ताकतों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने को कमज़ोर देशों की अर्थव्यवस्थाओं और संसाधनों को आपस में बांट लिया। रूस, जिसके पास असीम भूमि है, यूक्रेन को पाना चाहता है—जिसे उसने सोवियत संघ के विघटन के साथ खो दिया था। यूक्रेन अपने मानव संसाधन, ज़मीन, परमाणु स्रोत और समुद्र तक पहुंच मार्ग के मामले में बहुत समृद्ध है, और रूस इसे पाना चाहता है। हमला करने का मौका तब मिला जब आशंका फलीभूत हुई कि नाटो यूक्रेन के जरिए रूस बॉर्डर तक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। नाटो को भी यूक्रेन में वैसा ही मौका दिखा और वह भी उसके संसाधनों को बांटना चाहता है, जिसमें अमेरिकी स्पष्ट रूप से युद्ध का हर्जाना मांग रहा है। तरीका व परिणाम वही पुराना, युद्ध का तांडव।

वेनेजुएला, अपने विशाल तेल भंडारों के साथ, अमेरिका के लिए आसान शिकार रहा। क्यूबा और ग्रीनलैंड अब सूची में अगले क्रम में हैं। वहीं इस्राइल मध्य-पूर्व को मर्ज़ी मुताबिक ढालना चाहता है, वहीं ईरान की अपनी योजना है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर पूर्व-हमला कर दिया था, वैसे ही अमेरिकियों-इस्राइलियों ने ईरान को न्यूक्लियर बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण से रोकने को उस पर वार किया। तेल समृद्ध खाड़ी देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और इसलिए नुकसान झेल रहे हैं, वैसे ही जैसे ईरान की अप्रत्याशित युद्ध नीति व प्रतिक्रिया के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था हानि झेल रही है। बीते जमाने में, युद्ध थमने के बाद संधियों और संगठनों के जरिये आशा की किरण जगी : बतौर लीग ऑफ नेशन्स के उत्तराधिकारी राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा यकीनी बनाए रखने के उद्देश्य से हुई; द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए विश्व बैंक समूह (पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक) की स्थापना की गई; व्यापार में अड़चनें कम करने को विश्व व्यापार संगठन (मूलतः जीएटीटी, टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य संधि) बनाया; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया; विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य का समन्वय था; लंबी सूची में यूनिसेफ, यूनेस्को, आदि कई संगठन, संस्थान हैं, जिनके जरिये तत्कालीन नेतृत्व ने अतीत की गलतियां व भूलें सुधारने का प्रयास किया।

इस घटनाक्रम में महान नेतृत्व भी पाया- हैरी एस. ट्रूमैन ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान लागू किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका का नेतृत्व किया। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल ने न केवल युद्ध के दौरान नेतृत्व किया, बल्कि युद्धोत्तर व्यवस्था के गठन में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उनके द्वारा गढ़ा 'आयरन कर्टेन' विशेषण भी शामिल है। चार्ल्स डी गॉल ने पांचवें गणराज्य की स्थापना की और फ्रांस को एक पराजित राष्ट्र से यूरोप की मुख्य शक्ति में बदला। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में नेतृत्व किया, वहीं युद्धोत्तर पुनर्निर्माण व पूर्वी धड़े की स्थापना में योगदान दिया। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न थीं, लेकिन वे अपने-अपने देशों के महान नेता थे। आज, लगता है कि दुनिया 20वीं सदी के आरंभिक दौर में लौट गई है, जहां नेता दूसरे देशों को 'हड़पने' और 'नष्ट करने' की बातें कर रहे हैं-हमारे समय का नैतिक मार्गदर्शन कहां गया? उपरोक्त अधिकांश संगठनों को कमजोर होने दिया गया और आज वे अपने पूर्व स्वरूप का ढांचा व परछाई मात्र हैं। अमेरिका पूर्ण वर्चस्व दिखा रहा और सदियों पुराने नाटो सहयोगियों तक को मान्यता से इनकार कर रहा है। वैश्विक व्यापार समझौते बीते जमाने की बात हो गए, क्योंकि अमेरिका एकतरफा टैरिफ लगा रहा और अलग-अलग देश अस्तित्व की खातिर व्यापारिक गठबंधन बना रहे हैं। चीन और रूस अपनी अलग धुन पर चल रहे और दुनिया के हिस्से हथिया रहे हैं। फिर तकनीक विशेषज्ञ विशाल कंपनियों के बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पास निजी सोच लागू करने के लिए अकल्पनीय पैसा और संसाधन हैं... सत्ता चंद लोगों के हाथों में सिमट गई, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, 'सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है'। एपस्टीन फाइलों में नामों की सूची नैतिक पतन दर्शाती है। देशों के बीच फिर संतुलन स्थापना की ज़रूरत है। जैसे-जैसे बड़ी ताकतें अपने खेल खेलेंगी, वे दूसरे देशों को भी युद्ध के भंवर में खींच लेंगी। समय आ गया कि हम पुराने सहयोगियों को ध्यान में रख अपनी रणनीतिक दिशा तय करें और देश को सुरक्षित रखने को नए गठबंधन भी बनाएं। भारत ने सदा अंतर्राष्ट्रीय राय व दिशा तय करने में क्षमता से कहीं ज़्यादा जाकर भूमिका निभाई। आज, हमें संतुलन स्थापना की अपनी पुरानी आवाज़ और नैतिक ईमानदारी ढूंढ़नी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि यह देश के अंदर और विदेशी संबंधों, दोनों में ही गूंजे। मुश्किलों भरे मौजूदा समय से पार पाने को यह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष और युद्ध के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और आंतरिक-बाह्य सुरक्षा, दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा है।

प्रेरणा

मधुर वाणी का चमत्कार और जीवन में उसका प्रभाव

मानव जीवन में कई ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊँचाइयों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है वाणी की मधुरता। वाणी केवल शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार, विचार और आंतरिक भावनाओं का प्रत्यक्ष रूप होती है। जिस प्रकार मीठा फल शरीर को तृप्त करता है, उसी प्रकार मधुर वाणी मन को संतुष्टि और शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही संत-महात्मा वाणी की मिठास को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण मानते आए हैं।

एक समय की बात है, एक संत थे जिनका नाम आत्मदेव था। उनके पांच शिष्य थे, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। एक दिन संत आत्मदेव ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि वे जल्द ही उनकी परीक्षा लेंगे और जो इस परीक्षा में सफल होगा, वही उनका सच्चा और योग्य शिष्य कहलाएगा। यह सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो गए और उन्होंने पूरी लगन के साथ परीक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद संत आत्मदेव ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा कि अब परीक्षा का समय आ गया है। उन्होंने शिष्यों से एक सरल लेकिन गूढ़ प्रश्न पूछा, "बताओ इस संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है?" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को दो घंटे के भीतर इसका उत्तर देना होगा। प्रश्न सुनते ही शिष्य प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत आसान प्रश्न है। पहले शिष्य ने कहा कि गन्ना सबसे मीठा होता है क्योंकि उससे निकलने वाला रस बहुत स्वादिष्ट होता है। दूसरे शिष्य ने शक्कर को सबसे मीठा बताया, क्योंकि उसका उपयोग हर प्रकार की मिठाई बनाने में होता है। तीसरे शिष्य ने गुड़ को सबसे मीठा कहा, जबकि चौथे शिष्य ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का नाम लेकर उन्हें सबसे मीठा बताया। पांचवां शिष्य भी अपने साथियों की तरह किसी न किसी खाने की वस्तु को सबसे मीठा बताने लगा।

संत आत्मदेव ने सभी के उत्तर ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं आया। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा कि तुम सभी ने जो उत्तर दिए हैं, वे सही तो हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हैं। ये सभी वस्तुएं केवल हमारी जीभ को कुछ समय के लिए मिठास का अनुभव कराती हैं, लेकिन इनकी मिठास स्थायी नहीं होती। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताया कि इस संसार में सबसे मीठी चीज वाणी की मिठास है।

उन्होंने समझाया कि वाणी की मिठास वह शक्ति है जो मनुष्य को सम्मान दिलाती है और उसे लोगों के हृदय में स्थान देती है। एक व्यक्ति की पहचान केवल उसके कार्यों से ही नहीं, बल्कि उसकी वाणी से भी होती है। यदि किसी की वाणी मधुर है, तो वह बिना किसी प्रयास के ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। उसकी बातों में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग उसे सुनना पसंद करते हैं और उसके साथ समय बिताना चाहते हैं।

इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की वाणी कठोर और कटु होती है, तो वह अपने ही शब्दों से अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। कटु वचन किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं और संबंधों में दूरियां पैदा कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि केवल कुछ कठोर शब्दों के कारण गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करें।

वाणी की मधुरता का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक संबंध हों या व्यावसायिक क्षेत्र, हर जगह मधुर वाणी का महत्व होता है। एक मधुर भाषी व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखता है। वह अपने मित्रों और सहकर्मियों के बीच भी प्रिय होता है और सभी लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं।

मधुर वाणी केवल दूसरों को खुश करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखती है। जब हम विनम्रता और शांति के साथ बात करते हैं, तो हमारे भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि वाणी की मिठास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें सच्चाई और ईमानदारी भी हो। यदि हमारे शब्द मधुर हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं है, तो वे अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शब्दों में सच्चाई, संवेदनशीलता और सम्मान को बनाए रखें।

वर्तमान समय में जब लोग व्यस्तता और तनाव के कारण एक-दूसरे से रूखेपन से बात करने लगे हैं, तब वाणी की मधुरता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ी सी भी मिठास ला दें, तो हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बना सकते हैं। हमारी एक छोटी सी मुस्कान और मधुर वाणी किसी के दिन को बेहतर बना सकती है।

वाणी की मिठास को अपनाने के लिए हमें अपने भीतर धैर्य और आत्मसंयम विकसित करना होगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें क्रोध आता है, लेकिन यदि हम उस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लें, तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यही आत्मसंयम हमें एक सच्चा और परिपक्व व्यक्ति बनाता है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि वाणी की मधुरता जीवन का एक अनमोल गुण है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि हमें समाज में सम्मान और प्रेम भी दिलाती है। संत आत्मदेव की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि सच्ची मिठास किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे शब्दों में होती है। यदि हम अपनी वाणी को मधुर बना लें, तो हम न केवल अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हैं। यही सच्चे अर्थों में एक सफल और सार्थक जीवन की पहचान है।

धार्मिक स्थलों को क्यों नही मिलती बंदरों से मुक्ति

धार्मिक स्थलों को बंदरों से क्यों नही मिलती मुक्ति। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि इन स्थानों पर आने वाले श्रृद्धालु कब तक इनके आंतक झेलते रहेंगे? कब तक इनका शिकार होते रहेंगे? हाल में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु अपने कार्यकाल में 19 मार्च को वृंदावन आईं। वे दूसरी बार यहां आईं है। इससे पहले इसी पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी व रामनाथ कोविंद भी अपने कार्यकाल में दो बार वृंदावन आए थे। लेकिन, राष्ट्रपति मुर्मु वृंदावन के तीन दिवसीय प्रवास पर आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह एक बार वृंदावन आए। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, आर वेंकटरामन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वृंदावन अपनी धार्मिक यात्रा पर आ चुके हैं।

निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दो बार वृंदावन आए। आश्रय सदन में वृद्ध विधवा माताओं से मुलाकात करने आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते प्रणब मुखर्जी पहली बार 16 नवंबर 2014 को अक्षयपात्र में चंद्रोदय मंदिर के भूमि पूजन में आए तो दूसरी बार 18 नवंबर 2015 को चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमनोत्सव के पांच सौ वे वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते ज्ञानी जैल सिंह 1987 में वृंदावन आए और रंगजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे 1957 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद वृंदावन आए। उप राष्ट्रपति पद पर रहते 1985 में आर वेंकटरामन, 1993 में डॉ. शंकरदयाल शर्मा, 1959 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन वृंदावन आ चुके हैं। राष्ट्रपति या कोई वीवीआईपी जब भी वृंदावन आता है। प्रत्येक बार उनकी सुरक्षा तो होती ही है। सबसे बड़ा काम होता है वीवीआईपी को यहां के झपटमार बदंर से बचाना। ये बंदर झपटामार कर श्रद्धालु का चश्मा उतारते और किसी ऊंची जगह पेड़ या दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं। ये चश्मा तभी लौटाते हैं जब उन्हें खाने के लिए फ्रूटी, केला या दूसरे खाने के सामान दिए जाएं। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए प्रशासन लंगूरों के जगहजगह कट आउट लगवाता है। माना जाता है कि लंगूर से बंदर डरतें हैं। उन्हें डराने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ जगह लंगूर भी लाकर बांध दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की सुरक्षा से लेकर रूट पर व्यवस्थाओं को दुरस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने रात दिन एक कर दिया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के दौरे को देखते एक प्रशासन ने लंगूरों के जगह जगह कट आउट लगवाए।

लेखक को चित्रकूट में हनुमान गढ़ी जाने का अवसर मिला। वहां रास्ते में बंदर और लंगूर मिलते और आपके कपड़े और बैग पकड़कर रोक लेते हैं। वे आपके बैग और जेब से खाने का सामान प्रसाद आदि निकालकर ही आपको आगे जाने देते हैं। शुक्रताल में तो हनुमान धाम में बंदरों को भगाने के लिए लंगूर बांधा हुआ था। बंदर उसके अभयस्त हो गए थे। उन्हें पता था कि रस्सी में बंधे लंगूर की पंहुच कहां तक हैं। बदंर आते और लंगूर की पंहुच की दूरी से अगल रहकर लौट जाते।

प्रश्न है कि वीवीआईपी के आने पर ही क्यों बंदरों को रोकने की व्यवस्था होती है। देश के आम आदमी को भी वीवीआईपी क्यों नही समझा जाता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। उसके लिए क्यों नही ऐसी व्यवस्थाएं होती। बंदर हम हिंदुओं की श्रद्धा है। हम उसे पवित्र मानते हैं। पूजनीय मानते है। इतना होने पर भी उसके भोजन की व्यवस्था क्यों नही करते। अयोध्या में बड़ी तादाद में बंदर है। हनुमान गढ़ी पर मैंने बंदरों को फूलों की माला तोड़कर उसमें भोजन के अंश तलाशते देखा है। इसी शहर में डस्टविन से भोजन खोजते बंदर मुझे मिलें हैं। हमारी समाज सेवी संस्थाए क्यों नही इनके भोजन की जरूरत पूरी करती। बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढती बंदरों की जनसंख्या को भोजन चाहिए। भोजन ने मिलने वह निरीह प्राणी अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा। बंदरों के आतंक के कारण कई शहरों में तो महिलाओं और बच्चों का छतों पर जाना कठिन हो गया है। शहरों की नही अब तो जंगल में भी इनकी बढ़ती आबादी किसानों के लिए संकट बन चुकी है। भोजन के अभाव में बंदर खेतों की फसल तोड़कर खा रहे हैं। गेंहू की बाली खा जाते है। बोए गए गन्ने के बीज जमीन से निकाल कर वे अपनी उदरपूर्ति कर रहे हैं। किसान फसल की रक्षा को लेकर परेशान हैं। अब तो किसानों ने खेतों की रक्षा के लिए नौकर रखने शुरू कर दिए हैं।

आज बंदरों का आंतक धार्मिक स्थलों के साथ अन्य स्थानों पर भी बढ़ता जा रहा है। शहरी आबादी के साथ किसान भी परेशान है। आज जरूरी हो गया है कि सरकार द्वारा बंदरों की आबादी कम करने के लिए अभियान चलाया जाए। बंदरों के ग्रुप लीडर की नसंबदी कराकर उनकी आबादी नियंत्रित की जाए। जनता के शोर मचाने पर बंदरों का पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाना कोई स्थायी निदान नही है। ये जंगल और वनों से लौटकर फिर आबादी की ओर आ जाते हैं। बढ़ती बंदरों की आबादी को भोजन चाहिए। भोजन न मिलने पर उन्हें भी पेट भरना है। जैसे आदमी अपनी भोजन की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे साधन ढूंढ़ता है। वैसे ही आज बंदर कर रहे हैं। तीर्थ स्थलों पर चश्मा छीन रहे हैं तो कुछ जगह श्रद्धालुओं को पकड़कर उनके बैग से भोजन ले रहे हैं। गांव और शहरों में भोजन के लिए कपड़े उठाकर ले जाना आम बात है। ये उठाए गए कपड़े तब छोड़ते हैं, जब उन्हें खाने की सामग्री मिल जाए।

अभियान

श्रीकृष्ण की अर्धांगिनी यमुना जी और उनकी दिव्य लीलाओं की अमृत कथा

सनातन परंपरा में नदियों को केवल जलधारा नहीं, बल्कि चेतना, करुणा और मोक्ष की प्रवाहित शक्ति के रूप में देखा गया है। इसी दिव्य परंपरा में यमुना जी का स्थान अत्यंत विशेष है, जिन्हें परमब्रह्म श्रीकृष्ण की अर्धांगिनी और पटरानी के रूप में सम्मानित किया गया है। यमुना केवल एक नदी नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति की वह अमृतधारा हैं, जो युगों से भक्तों के हृदय को शीतल और पवित्र करती आ रही हैं। उनका स्वरूप प्रेम, समर्पण और दिव्यता का ऐसा संगम है, जिसमें डूबकर साधक आत्मिक शांति का अनुभव करता है।

पुराणों के अनुसार, यमुना जी का अवतरण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, जिसे यमुना जयंती या यमुना षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह चैत्र नवरात्र के मध्य आता है, जब सृष्टि में नवजीवन का संचार होता है। इसी कालखंड में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार यमुना जी का अवतरण सृष्टि के नवप्रारंभ और दिव्य ऊर्जा के प्रस्फुटन का प्रतीक माना जाता है। यमुना जी के जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक और भावपूर्ण है। वे सूर्यदेव की पुत्री हैं और उनकी माता संज्ञा, जो विश्वकर्मा की पुत्री थीं। उनके भाई यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और शनिदेव उनके छोटे भाई हैं, जो कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। इस प्रकार यमुना जी का संबंध धर्म, न्याय और जीवन-मृत्यु के गूढ़ सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। किंतु इन सबके बीच उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, करुणामयी और प्रेममयी है।

एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा के अनुसार, यमुना जी ने कालिंदी रूप में कठोर तपस्या की थी। वे भगवान श्रीकृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने हिमालय के समीप कालिंदी पर्वत के पास घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनका हाथ थामकर उन्हें अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। यह कथा उनके अटूट प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

जब भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और वृंदावन में अपने बाल्यकाल की लीलाएं कीं, तब यमुना जी हर क्षण उनके साथ रहीं। एक कथा के अनुसार, जब वसुदेव जी नवजात श्रीकृष्ण को कंस के भय से गोकुल ले जा रहे थे, तब उन्हें यमुना नदी को पार करना था। उस समय यमुना का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने श्रीकृष्ण को अपनी गोद में लेकर जल में प्रवेश किया, यमुना जी ने अपने प्रवाह को शांत कर दिया और उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए जल ऊपर उठाया। यह दृश्य अत्यंत भावुक और दिव्य था, जिसमें यमुना जी ने अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की।

एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि वृंदावन में कालिय नाग नामक एक विषैला सर्प यमुना में निवास करता था, जिससे जल विषाक्त हो गया था और लोग भयभीत रहते थे। तब श्रीकृष्ण ने यमुना में कूदकर कालिय नाग का मर्दन किया और उसे वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद यमुना का जल पुनः पवित्र और निर्मल हो गया। इस कथा में यमुना जी की पीड़ा और श्रीकृष्ण द्वारा उनकी रक्षा का सुंदर चित्रण मिलता है।

ब्रजभूमि में यमुना जी का महत्व केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि श्रीराधा-कृष्ण की लीलाओं की साक्षी और सहभागी के रूप में है। उनके तट पर रासलीला, झूलन, होली और अनेक उत्सव आयोजित होते थे, जिनमें यमुना जी का सान्निध्य विशेष महत्व रखता था। उनके तटों पर स्थित कुंज और उपवन प्रेम और भक्ति की अनगिनत कहानियों को संजोए हुए हैं।

यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, जो हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वहां से निकलकर वे उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होकर प्रयागराज में गंगा और सरस्वती के संगम में मिल जाती हैं। यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यमुना जी का जल श्यामल और शांत होता है, जो उनके नाम कालिंदी को सार्थक बनाता है। यह श्यामलता श्रीकृष्ण के स्वरूप से भी मेल खाती है, जिससे उनका संबंध और अधिक गहरा हो जाता है। उनके तटों पर बैठकर ध्यान करने से मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जो साधक को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।

यमुना जयंती के अवसर पर देश भर में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में इस दिन भव्य आयोजन होते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है, भजन-कीर्तन होते हैं और यमुना जी की आरती की जाती है। भक्तजन उनके तट पर दीपदान करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

आज के समय में, जब नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं, तब यमुना जी की महिमा को समझना और उनके संरक्षण का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि हम उन्हें वास्तव में देवी मानते हैं, तो हमें उनके जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।

अंततः यमुना जी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, समर्पण और पवित्रता का कितना महत्व है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने भीतर की दिव्यता को बनाए रखना चाहिए। श्रीकृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में उनका स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक है। यमुना जी की भक्ति और उनका स्मरण मनुष्य को आत्मिक उन्नति और परम शांति की ओर ले जाता है, यही उनकी सच्ची महिमा है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

‘सुगम डिजिटल गुजरात’ : लाइन से ऑनलाइन की ओर जन सुख-सुविधा का एक और कदम

- विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात : टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुशासन का संकल्प
- मुख्यमंत्री की नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
- डिजिटलाइजेशन वर्तमान भारत, वर्तमान गुजरात तथा वर्तमान नेतृत्व की देन है : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जनता के काम आसानी से हों, लोगों के काम जितनी आसानी से होंगे, उतना ही शासन-प्रशासन को अधिक संतोष मिलेगा
- जनता, निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी जब सभी स्तर पर साथ मिलकर काम करते हैं, तब परिणाम हमेशा अद्भुत एवं सटीक आता है
- सब साथ हैं, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली है, राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गरिमामय उपस्थिति में मंगलवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में राज्य के प्रशासन को अधिक आधुनिक तथा नागरिक-केन्द्रित बनाने के उद्देश्य के साथ ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पहल का विधिवत् प्रारंभ कराया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ संकल्प को साकार करने तथा गुजरात के नागरिकों को सरकारी सेवाएँ उंगलियों पर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है।
इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) की पाँचवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राज्य के 5 प्रमुख विभागों की 20 हाईइंपैक्ट सेवाओं का ऑनलाइन सरलीकरण घोषित किया गया था। इस पहल द्वारा अब आय-जाति के प्रमाणपत्र, राशन कार्ड तथा शपथपत्र जैसी बुनियादी सेवाएं ‘फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस’ बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ अनावरण कार्यक्रम अंतर्गत कहा कि हम कई कार्यक्रम किया करते हैं और कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार जो कार्य करती है, वे लोगों तक पहुँचते हैं। इतना ही नहीं; सरकार का हमेशा यह प्रयास होता है कि जो कार्य किया गया है, उसमें कमी न रह जाए और प्रेस के माध्यम से वह जानकारी घर-घर पहुँचे, तो जो नागरिक सरकारी योजनाओं के पात्र हैं, वे उसका पूरा लाभ ले सकें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2002 में ‘स्वागत ऑनलाइन’ कार्यक्रम शुरू कर टेक्नोलॉजी के उपयोग को सदैव प्राथमिकता दी है। उसी प्राथमिकता के आधार पर आज हम बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और हम लगभग 20 नई सेवाएँ ‘लाइन’ से ‘ऑनलाइन’ करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को घर बैठे सुविधा मिले; इसके लिए फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार प्रयासरत है। इस डिजिटल प्रक्रिया में यदि नागरिकों को कहीं भी दिक्कत महसूस हो, तो उसके निवारण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।
श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण जनों के सबसे पहले पटवारी या विलेज कम्प्यूटर एंटरप्रेन्योर (वीसीई) के साथ ही संपर्क में आने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी सेवाएँ ऑनलाइन किस तरह मिलती हैं; उसका हम सभी जितना प्रचार-प्रसार करेंगे, उतना ही जनता को और प्रशासन को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “आप जो नौकरी या सेवा कार्य करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही दिशा में होना चाहिए कि जनता के काम आसान हों। हमारे मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जितनी आसानी से लोगों का काम हो, उतना हमें संतोष मिले। जब जन प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी सभी स्तर एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं, तब उसका परिणाम अद्भुत आता है। गुजरात में हम सबने देखा है कि कैसी भी स्थिति हो, अगर हमने साथ मिलकर काम किया है, तो उसके सटीक परिणाम मिले हैं।”
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट की बात की थी, तब कई लोगों को ऐसा लगता था कि यह कैसे संभव होगा, परंतु आज पूरे देश में सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट का उपयोग सामान्य नागरिक तथा छोटे से छोटे व्यक्ति कर रहे हैं। इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि जब सरकार समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रही हो, तब जनता का साथ हमेशा मिलता रहा है। आज 20 सेवाएँ ऑनलाइन की गई हैं और भविष्य में इस क्षेत्र में ध्यान देकर नागरिकों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार तत्पर है।
उन्होंने बताया कि अनावृत हो रही इस नई पहल से स्थापित होने वाली व्यवस्था में डेटा डिजिटल होने के कारण नागरिक को हर नई सेवा के लिए बार-बार वही के वही पेपर प्रस्तुत नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए डिजिटल लॉकर की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस उपयोग का लाभ जन-जन तक पहुँचे; इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात’ विजन को साकार करने के लिए हम सबको डिजिटल क्षेत्र में अधिक से अधिक आगे बढ़ना है। यूपीआई का सर्वाधिक उपयोग छोटे फेरीवाले तथा सब्जीवाले जैसे कम पढ़े-लिखे लोग कर रहे हैं। डिजिटल सरलीकरण के जरिये नागरिक सेवाएँ अधिकाधिक आसान बनाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने हाल में उत्पन्न हुई वैश्विक स्थिति के विषय में कहा कि आज राज्य में डीजल, पेट्रोल या गैस की कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और मिलता रहेगा। सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के कार्य मंत्र के साथ सरकार विकसित गुजरात के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सब साथ हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि डिजिटलाइजेशन वर्तमान भारत, वर्तमान गुजरात तथा वर्तमान नेतृत्व की देन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नागरिकों एवं सरकार के बीच दूरी कम करने के प्रयास शुरू किए गए थे। नागरिकों को जन हितकारी सुविधाएँ आसानी से मुहैया कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया था।
उन्होंने कहा कि गाँव में सीएचसी, पीएचसी तथा शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ये सेवाएँ तेजी से मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तमाम नागरिक-केन्द्रित सेवाएँ डिजिटल बनाने की शुरुआत की है।
उन्होंने जोड़ा कि पहले दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता, तो 15 या 16 पैसे ही नागरिकों तक पहुँचते; जबकि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुदृढ़तम नागरिकों को सीधे डीबीटी के जरिये पूरी सहायता मिल रही है। इस बार बेमौसम वर्षा प्रभावित किसानों के खाते में एक क्लिक से लगभग 11000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जबकि समर्थन मूल्य पर 15000 करोड़ रुपए की फसलें खरीदी गई। इसके अलावा; 26 हजार करोड़ रुपए एक ही क्लिक से सभी लाभार्थियों के खाते में जमा हो गए। आज शायद यह डिजिटल सिस्टम न होता, तो पूरी राज्य सरकार के पाँच-छह लाख कर्मचारी इन कार्यों में लगाने पड़ते।
आज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की सेवाएँ, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तथा विधवा बहनों की पेंशन जैसी सुविधाएँ डिजिटलाइजेशन होने के कारण आसान, पारदर्शी तथा त्वरित बनी हैं। ये सेवाएँ पूरी तरह डिजिटल नहीं हैं, कुछ दस्तावेज ऑफलाइन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यह पोर्टल कार्यरत होने से नागरिक घर बैठे अधिकांश सेवाओं के लिए फॉर्म स्वयं ही भर सकेंगे। ‘नागरिक देवो भव’ के भाव से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में शुरू हुई इस डिजिटल सुविधाओं का योगदान विकसित भारत-2047 में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आग्रह है कि आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रमाणपत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों में और सरकारी कार्य के लिए आने वाले लोगों की लाइनें खत्म होनी चाहिए। लोगों का काम घर बैठे होना चाहिए। हर वर्ष अस्सी लाख लोग कतार में खड़े रहें; यह उचित नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा सहित सभी विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं।
‘सुगम डिजिटल गुजरात’ की विशेषता के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों के काम घर बैठे होंगे। सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। नागरिकों को फोन में, व्हॉट्सएप पर सब मिलेगा। इसमें बारकोड है तथा आधार कार्ड आधारित ऑथेंटिफिकेशन है। यह सिस्टम इस तरह तैयार और विकसित किया गया है कि अगर एक साथ दस लाख लोग पोर्टल पर आ जाएँ, तो भी समस्या नहीं पैदा होगी। उन्होंने राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध होने का उल्लेख करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया कि वे यदि सरकार को कोई नया सिस्टम विकसित करने की जरूरत हो, तो उसे लेकर सुझाव दें।
इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशिक्षण) के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला ने सुगम डिजिटल गुजरात के बारे में कहा कि समग्र प्रक्रिया के मनोमंथन तथा अध्ययन रिपोर्ट के बाद ये टॉप 20 सर्विसेज नागरिकों की सुविधा के लिए कार्यान्वित की गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री मोना खंधार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती, राज्य सरकार के उच्चाधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार तथा पटवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल का माल लदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन,50 मिलियन टन का आंकड़ा किया पार

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल लदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 23 मार्च 2026 तक 50.10 मिलियन टन (MT) का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 मिलियन टन अधिक है, जो मंडल की सतत प्रगति एवं कार्यकुशलता को दर्शाता है।मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में अहमदाबाद मंडल के परिचालन एवं वाणिज्य विभागो की टीम द्वारा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों—जैसे रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, त्वरित निर्णय प्रक्रिया एवं संसाधनों का इष्टतम उपयोग—ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंडल द्वारा 50.38 मिलियन टन का सर्वोच्च लदान दर्ज किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः 50 मिलियन टन का आंकड़ा पार करना अहमदाबाद मंडल की निरंतर प्रगति एवं उच्च कार्य निष्पादन क्षमता को दर्शाता है।
अहमदाबाद मंडल द्वारा मालगाड़ियों के सुचारु एवं समयबद्ध संचालन, रेक की प्रभावी उपलब्धता एवं उपयोग, टर्नअराउंड समय में कमी तथा लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। साथ ही, ग्राहकों के साथ सतत संवाद, नई संभावनाओं की पहचान एवं ग्राहक-अनुकूल सेवाओं के विस्तार से माल लदान में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की गई है।
अहमदाबाद मंडल द्वारा कोयला, सीमेंट, उर्वरक, कंटेनर एवं पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न वस्तुओं के लदान में निरंतर

वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है।
यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे की “परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहक संतुष्टि एवं सतत विकास” की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है एवं यह उपलब्धि मंडल की सुदृढ़ कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं समन्वित प्रयासों का प्रतिफल है।

भावनगर रेलवे मंडल में ‘चालक दल हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे’ सफलतापूर्वक संपन्न

(जीएनएस)। रेल कर्मचारियों के कार्य-संतोष एवं कार्य-परिस्थितियों के आकलन हेतु भावनगर मंडल द्वारा “चालक दल हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे” का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य रनिंग स्टाफ (चालक दल) के बीच संतुष्टि स्तर को मापना तथा कार्यस्थल पर सुधार के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करना था। सर्वे के परिणामों के अनुसार विभिन्न स्टेशनों/लोको शेड्स पर चालक दल संतुष्टि का स्तर अत्यंत उत्साहजनक रहा। प्रमुख स्थानों पर प्राप्त प्रतिशत इस प्रकार हैं— जूनागढ़ लॉबी– 97.29%, बोटाद लॉबी– 90.17%, सुरेन्द्रनगर गेट लॉबी @सुरेन्द्रनगर स्टेशन– 89.46%, पोरबंदर लॉबी– 88.43%, भावनगर टर्मिनस लॉबी– 87.42%, वेरावल लॉबी– 86.76%, JCLR लॉबी @ राजकोट स्टेशन 86.70% और जेतलसर लॉबी– 82.50% ।
इन परिणामों से स्पष्ट है कि भावनगर मंडल में कार्यरत चालक दल के बीच संतोष का स्तर उच्च है, जो सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन के लिए सकारात्मक संकेत है।
मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) श्री ऋत्विक शर्मा ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सर्वे से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ, ताकि कर्मचारियों के कार्य वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रकार के सर्वे भविष्य में भी नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे कर्मचारियों की अपेक्षाओं को समझकर संगठनात्मक दक्षता को और सुदृढ़ किया जा सके।

होर्मुज के साये में भी सुरक्षित भारत की रसोई: 92 हजार टन LPG के साथ बढ़ता भरोसा और कूटनीति का संतुलन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताएं गहराने लगती हैं, तब सबसे बड़ी चिंता उन देशों की होती है जो बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है, जहां रसोई गैस यानी एलपीजी करोड़ों घरों की जरूरत है। ऐसे संवेदनशील समय में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि Strait of Hormuz में तनाव के बावजूद देश की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल किसी भी प्रकार का तात्कालिक संकट नहीं है। हाल के दिनों में ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा कर दी थीं। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस परिवहन मार्गों में से एक है, वहां किसी भी प्रकार की बाधा का असर सीधे वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी संतुलित रणनीति और मजबूत लॉजिस्टिक्स के दम पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाए रखा है। राजेश सिन्हा, जो शिपिंग मंत्रालय में विशेष सचिव हैं, ने प्रेस वार्ता में साफ किया कि समुद्री मार्गों पर किसी भी देश द्वारा टैक्स या लेवी लगाए जाने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी कदम की अनुमति नहीं है और वैश्विक व्यापार को बाधित करने की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। यह बयान न केवल घरेलू स्तर पर भरोसा बढ़ाने वाला है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि स्थिति नियंत्रण में है। सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, ‘जग वसंत’ और ‘पाइन गैस’ नामक दो भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं। इन जहाजों में कुल 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इन टैंकरों पर लगभग 60 भारतीय नाविक सवार हैं, जिनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जहाज 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे, जिससे घरेलू आपूर्ति को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में भारत के झंडे वाले लगभग 20 जहाज मौजूद हैं, जिनमें से सभी सुरक्षित हैं। इनमें 5 टैंकर एलपीजी से भरे हुए हैं, जिनमें करीब 2.30 लाख मीट्रिक टन गैस है। एक अन्य टैंकर लोडिंग प्रक्रिया में है, जो यह दर्शाता है कि भारत की आपूर्ति श्रृंखला न केवल सक्रिय है, बल्कि निरंतर गतिशील भी बनी हुई है। सरकार इन सभी जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है।
यह पूरा परिदृश्य इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम किया है। विविध स्रोतों से आयात, रणनीतिक भंडारण और मजबूत समुद्री नेटवर्क ने देश को ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखने में मदद की है। एलपीजी जैसे आवश्यक ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम जनता के दैनिक जीवन से है।
कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। रणधीर जायसवाल, जो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत विभिन्न देशों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है। शीर्ष स्तर पर संपर्क और बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कूटनीतिक सक्रियता न केवल भारत के हितों की रक्षा करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी जिम्मेदार भूमिका को भी दर्शाती है।
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वैश्विक तनाव के संकेत मिलते ही आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी बढ़ा दी गई थी और वैकल्पिक मार्गों तथा स्रोतों पर भी ध्यान दिया गया। यही कारण है कि जब अन्य देशों में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है, तब भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू-राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत का यह संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण एक मजबूत उदाहरण के रूप में सामने आता है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। हालांकि, फिलहाल सरकार के आश्वासन और जमीनी स्तर पर दिख रही तैयारियों से यह स्पष्ट है कि भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।

फर्जी रेल टिकटों के विरुद्ध सघन जांच में अहमदाबाद मंडल को बड़ी सफलता,यात्रियों की सुरक्षा एवं पारदर्शी टिकटिंग प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु कड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा, मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में चलाए गए टिकट जांच अभियान के दौरान फर्जी रेल टिकटों के एक संगठित मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया है। यह कार्रवाई यात्रियों के हितों की सुरक्षा तथा रेलवे की पारदर्शी एवं विश्वसनीय टिकटिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनांक 21 मार्च 2026 को प्रयागराज–अहमदाबाद एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22968) के अहमदाबाद स्टेशन पर आगमन के दौरान नियमित टिकट जांच में तैनात टिकट जांच स्टाफ श्री नीरज मेहता, श्री साजी फिलिप एवं उनकी टीम द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए संदिग्ध यात्रियों को रोका गया। गहन जांच के दौरान दोनों यात्रियों के टिकटों का सीरियल नंबर एक समान पाया गया। तत्पश्चात क्यूआर कोड स्कैनिंग एवं तकनीकी सत्यापन में यह स्पष्ट हुआ कि टिकटों की प्रतियां अनधिकृत रूप से तैयार की गई थीं। इस प्रकरण में अहमदाबाद की टीम द्वारा 15 व्यक्ति पकड़े गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अलर्ट जारी किया गया तथा संबंधित विभागों एवं नियंत्रण कक्ष को सूचित कर समन्वित कार्रवाई प्रारंभ की गई। आगे की जांच में यह तथ्य सामने आया कि असली टिकटों को स्कैन कर उनकी कई प्रतियां तैयार कर यात्रियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। यह कृत्य प्रयागराज में एटीवीएम (ATVM) फैसिलिटेटर्स के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिससे न केवल यात्रियों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, बल्कि रेलवे राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इस प्रकरण में संबंधित एजेंसियों के सहयोग से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। दिनांक 21/22 मार्च की रात्रि लगभग 10:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक अहमदाबाद स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनु त्यागी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी रखी गई तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज में विजिलेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वित छापेमारी की गई।
इस दौरान सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर फर्जी टिकटों पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों की पहचान की गई। पकड़े गए 15 व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने पर उन्होंने अलग-अलग दो व्यक्तियों की पहचान की, जिनसे उन्होंने टिकट खरीदे थे। जांच में इन व्यक्तियों के नाम विनय शुक्ला एवं गौरव पांडे सामने आए।
आगे की जांच में यह भी पाया गया कि फैसिलिटेटर विनय शुक्ला ने दिनांक 20 मार्च को प्रयागराज टी-8 टर्मिनल से अहमदाबाद के 6 तथा सूरत के 5 असली टिकट निकाले थे, जिन्हें उसने अपने साथी फैसिलिटेटर गौरव पांडे को सौंपा। गौरव पांडे इन टिकटों को लेकर चौंक क्षेत्र में अपने सहयोगी फरहाद के पास पहुंचा, जहां महंगे स्कैनर एवं फोटोशॉप सेटअप की सहायता से इन टिकटों की हूबहू प्रतियां (प्रत्येक की 10-10 कॉपी) तैयार की गईं। इसके पश्चात शातिरों द्वारा असली टिकटों को काउंटर पर वापस जमा कर राशि का रिफंड प्राप्त कर लिया गया, जबकि उनकी तैयार की गई नकली प्रतियां यात्रियों को मूल मूल्य पर बेच दी गईं। इस प्रकार आरोपियों ने अवैध लाभ अर्जित करते हुए रेलवे राजस्व को क्षति पहुंचाई।
उक्त प्रकरण में गौरव पांडे, विनय शुक्ला एवं फरहाद के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अहमदाबाद मंडल के अधिकारियों ने टिकट जांच स्टाफ की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं टिकटिंग प्रणाली की शुचिता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध भविष्य में भी सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे केवल अधिकृत रेलवे काउंटर, अधिकृत एजेंट अथवा आधिकारिक डिजिटल माध्यमों के माध्यम से ही टिकट प्राप्त करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे प्रशासन को दें।

पश्चिम रेलवे द्वारा 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:
1. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 27 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09621 अजमेर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 26 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 11 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 13 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 12 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड–हिसार साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 04728 वलसाड–हिसार स्पेशल को 16 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड स्पेशल को 15 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
ट्रेन संख्या 09622, 04828, 09706 एवं 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 26.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर रेलवे मंडल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 24 मार्च 2026 को रेलवे कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा, सचिव श्रीमती माया त्रिपाठी एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन प्रमुख रूप से शामिल रहे।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण एवं प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत किए गए, साथ ही नारी के महत्व को चित्रित करते हुए एक गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों की बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पोस्टर/ड्रॉइंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। मंडल कार्यालय में कार्यरत महिला संविदा कर्मियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं की भूमिका, उनकी उपलब्धियों एवं समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डाला तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज: दिल्ली में फिर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और कई राज्यों में अलर्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में मौसम ने अचानक करवट लेकर गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राजधानी नई दिल्ली समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले 48 घंटों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह बदलाव अभी थमने वाला नहीं है और अगले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में फिर से बारिश, तेज हवाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

राजधानी दिल्ली में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन का तापमान संतुलित बना हुआ है। हालांकि आईएमडी ने संकेत दिया है कि गुरुवार के आसपास एक बार फिर मौसम करवट लेगा और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो तापमान में और गिरावट ला सकती हैं।

इस मौसम बदलाव के पीछे मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है। इसका असर राजस्थान में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश दर्ज की गई। हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 9 मिमी वर्षा

रिकॉर्ड हुई। सुबह से ही बादल, बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, भरतपुर और कोटा संभाग में आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि 26-27 मार्च को राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, 28 से 31 मार्च के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जो आंधी और तेज बारिश लेकर आ सकता है। अगर उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 से 28 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे ठंडक और बढ़ सकती है।

मैदानी इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 26 और 29 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इससे किसानों और आम लोगों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 24 से 28 मार्च के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 26 से 29 मार्च के बीच मौसम का मिजाज बदला रहेगा। यहां बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

मध्य भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। 26 और 27 मार्च को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र में 24 और 25 मार्च के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट और बादलों की आवाजाही से गर्मी से राहत मिल रही है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। यहां गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया गया है, जिससे मौसम सुहावना बना रह सकता है।

मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से साफ है कि आने वाले कुछ दिन देशभर में मौसम के लिहाज से काफी सक्रिय रहने वाले हैं। जहां एक ओर यह बदलाव गर्मी से राहत दिला रहा है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं, ओलावृष्टि और अचानक बारिश जैसी घटनाएं चुनौतियां भी लेकर आ सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मौसम बदलाव जलवायु परिवर्तन के संकेत भी हो सकते हैं, जहां मौसम का पैटर्न पहले से ज्यादा अनिश्चित और तीव्र होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

अंततः, अगले 48 घंटे देश के मौसम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। जहां कुछ क्षेत्रों में ठंडक और राहत मिलेगी, वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाएं और बारिश परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में सतर्कता और तैयारी ही इस बदलते मौसम से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है।

अफवाहों पर ब्रेक, आपूर्ति फुल टैंक: वडोदरा में पेट्रोल-डीजल और LPG को लेकर प्रशासन का भरोसा

(जीएनएस)। वडोदरा। हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में ईंधन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच वडोदरा जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें और किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। जिला आपूर्ति अधिकारी गीताबेन देसाई ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताते हुए कहा कि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार निगरानी की जा रही है।

जिले में ईंधन की उपलब्धता के आंकड़े भी इस भरोसे को मजबूत करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, वडोदरा में कुल 253 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। मंगलवार सुबह तक जिले में करीब 1699 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध था। हालांकि, अफवाहों के चलते एक दिन पहले अचानक मांग बढ़ गई और 1084 किलोलीटर पेट्रोल की बिक्री दर्ज की गई। इसी तरह डीजल का स्टॉक लगभग 2300 किलोलीटर है, जिसमें से 1049 किलोलीटर की खपत हुई। यह स्पष्ट संकेत है कि सप्लाई मजबूत है, लेकिन अफवाहों के कारण मांग में असामान्य उछाल देखा गया।

प्रशासन ने यह भी बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार अपने डिपो से ईंधन की आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी डिपो सुबह 6 बजे से सक्रिय हैं और जरूरत के अनुसार पेट्रोल पंपों तक ईंधन पहुंचाया जा रहा है। स्थिति को और बेहतर बनाए रखने के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आपूर्ति आधी रात तक जारी रहे, ताकि किसी भी पंप पर कमी की स्थिति उत्पन्न न हो। एलपीजी गैस को लेकर भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक बताई गई है। जिले में वर्तमान समय में करीब 21,347 सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि एक दिन पहले 14,118 सिलेंडरों का वितरण किया गया। यह आंकड़े दिखाते हैं कि घरेलू गैस की मांग भी पूरी तरह से पूरी की जा रही है और किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है।

इस बीच गोत्री क्षेत्र में खुले में पेट्रोल बिक्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। साथ ही, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर फील्ड निरीक्षण के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे पंपों को अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बाजार में अनुशासन बना रहे और आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर संकट की स्थिति को और गंभीर बना देती हैं। जब लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, तो कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि वास्तविकता में सप्लाई पर्याप्त होती है। वडोदरा प्रशासन की सक्रियता इस बात का उदाहरण है कि समय रहते सही जानकारी देकर इस तरह की स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

अंत में जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, संयम से काम लेने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और भविष्य में भी इसे बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

सूरत की संवेदनशीलता ने फिर रचा इतिहास: क्रुणालभाई के अंगदान से चार जिंदगियों में लौटी रोशनी

(जीएनएस)। सूरत। इंसानियत जब अपने सबसे ऊंचे स्वरूप में सामने आती है, तो वह केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। सूरत में एक बार फिर ऐसा ही मानवीय उदाहरण देखने को मिला, जहां 20 वर्षीय क्रुणालभाई जादव के अंगदान ने चार जरूरतमंद लोगों को नई जिंदगी देने का रास्ता खोल दिया। "ऑर्गन डोनर सिटी" के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुके सूरत ने इस घटना के साथ मानवता की एक और मिसाल कायम की है।

नवसारी जिले के वांसदा के चिकलिया गांव के निवासी क्रुणालभाई का जीवन एक सड़क दुर्घटना के बाद अचानक बदल गया। 18 मार्च को उनकी बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पहले वांसदा और फिर वलसाड सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत में रेफर किया गया।

डॉक्टरों की पूरी टीम ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 23 मार्च को विशेषज्ञों ने उन्हें ब्रेन-डेड घोषित कर दिया। यह वह क्षण था, जब एक परिवार के लिए सबसे कठिन निर्णय सामने था। लेकिन यहीं से एक नई उम्मीद की शुरुआत भी हुई। अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने परिजनों को अंगदान के महत्व के बारे में समझाया। भारी मन से, लेकिन बड़े दिल के साथ, क्रुणालभाई के माता-पिता ने अपने बेटे के अंग दान करने का निर्णय लिया।

उनके शब्द हर किसी को भावुक कर देने वाले थे—"अगर हमारे बेटे के अंगों से किसी की जान बचती है, तो वह दूसरों के शरीर में जीवित रहेगा।" यह निर्णय केवल एक परिवार का साहस नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि जीवन के बाद भी हम दूसरों के लिए जी सकते हैं।

अंगदान की प्रक्रिया पूरी तरह से सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से संपन्न की गई। क्रुणालभाई का हृदय अहमदाबाद स्थित यू.एन. मेहता अस्पताल भेजा गया, जबकि उनका लिवर और दोनों किडनी आई.के.डी. अस्पताल पहुंचाई गईं। इन अंगों के जरिए चार अलग-अलग मरीजों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। यह एक ऐसा क्षण है, जहां एक व्यक्ति का अंत कई लोगों के लिए नई शुरुआत बन जाता है।

पूरी प्रक्रिया के दौरान अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा टीम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। डॉ. धारिणी परमार के नेतृत्व में, डॉ. केतन नायक, डॉ. नीलेश कछड़िया और इकबाल कड़ीवाला के मार्गदर्शन में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों ने मिलकर इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह समन्वय ही है, जो ऐसे संवेदनशील मामलों को संभव बनाता है।

न्यू सिविल हॉस्पिटल के जरिए यह 92वां अंगदान दर्ज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सूरत में अंगदान को लेकर जागरूकता और सकारात्मक सोच लगातार बढ़ रही है। यहां के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवनदान का सबसे बड़ा माध्यम है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अभी भी अंगदान को लेकर जागरूकता की कमी है, जबकि हर साल हजारों लोग अंगों की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सूरत जैसे शहरों से सामने आने वाली कहानियां समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह घटना लोगों के मन में यह विश्वास जगाती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि "ऑर्गन डोनेशन महादान" केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, जो किसी के जीवन में नई उम्मीद, नई रोशनी और नया भविष्य लेकर आ सकती है। क्रुणालभाई का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दूसरों को जीने का अवसर दिया।

अंततः, यह कहानी केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है।

राजकोट में खाद्य सुरक्षा का मजबूत मॉडल: 11.81 लाख लोगों तक पहुंचा मुफ्त अनाज, योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने

(जीएनएस)। राजकोट। आम नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राजकोट जिले ने एक मजबूत और प्रभावी उदाहरण पेश किया है। हाल ही में शहर-जिला सिविल सप्लाई एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. ओम प्रकाश ने की, जिसमें जिले की आपूर्ति व्यवस्था, खाद्य वितरण प्रणाली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में सबसे प्रमुख चर्चा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लेकर रही। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत अब तक जिले के 11,81,150 लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरित किया जा चुका है। यह आंकड़ा न केवल योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रशासनिक स्तर पर इसे कितनी गंभीरता से लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) के तहत जिले में कुल 3,04,020 राशन कार्ड पंजीकृत हैं। यह संख्या इस बात का संकेत है कि बड़ी आबादी सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर निर्भर है। ऐसे में इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय (AAY) और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) श्रेणी के परिवारों को नियमित रूप से गेहूं और चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय कार्डधारकों को उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशन भी दिया जा रहा है। यह व्यवस्था समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाती है।

बैठक में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना की प्रगति भी प्रस्तुत की गई, जो देशभर में खाद्य वितरण प्रणाली को एकीकृत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। फरवरी के अंत तक इस योजना के तहत राजकोट जिले के 21,035 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया, जबकि अन्य जिलों के 12,716 और अन्य राज्यों के 1,947 लाभार्थियों को भी यहां राशन उपलब्ध कराया गया। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रवासी श्रमिकों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए यह योजना कितनी उपयोगी साबित हो रही है। डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए e-KYC प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 96.86 प्रतिशत e-KYC कार्य पूरा हो चुका है। इससे न केवल फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलती है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होता है। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के दौरान गैस आपूर्ति और निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान 173 कुकिंग गैस सिलेंडर जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई, जो यह संकेत देता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों पर सख्ती से नजर बनाए हुए है।

कक्षा 4 में भर्ती पर प्रतिबंध के कारण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रस्तुति

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात सरकार, गांधीनगर स्थित वित्त विभाग सचिवालय के संकल्प संख्या व्यय-102010-118-झ.1, दिनांक 14/08/2014 और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 01/04/2010 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दोनों संकल्पों को रद्द करने के लिए गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा, महासचिव सैयदभाई शेख, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, सूरत नगर शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल और अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 01/04/2010 के संकल्प के प्रावधानों के अनुसार, चालक और श्रेणी-4 चपरासी, चपरासी-कर्म-चालक, चपरासी-सह-परिचारक, माली, धोबी, चौकीदार आदि पदों पर भर्ती पर प्रतिबंध है। चपरासी-सह-चौकीदार, सफाईकर्मी, लिफ्टमैन, लिफ्ट अटेंडेंट, सफाईकर्मी, वार्डबॉय, ड्रेसर, आया, क्लीनर, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, स्ट्रेचर बेयरर, वाटर बेयरर, हेल्पर, मुकदम, कुक, असिस्टेंट कुक, पोर्टर, हीरो, हवलदार और ऐसे ही अन्य पदों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए। इसी कारण गुजरात राज्य में श्रेणी-4 के पदों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। जिसके चलते राज्य सरकार में उपरोक्त पदों को लंबे समय से खाली रखा गया है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है जो इन पदों पर नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि इन पदों पर अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा ही कार्यरत हैं। राज्य सरकार में ऐसे लाखों पद खाली पड़े हैं। जिसके चलते राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। इस स्थिति में गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस ने उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को रद्द करने की मांग की है। गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक निर्वाचित होने के बाद समाज के युवाओं की बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं करते। गुजरात सरकार में बड़ी संख्या में श्रेणी-4 के पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती 2010 से रुकी हुई है, फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित विधायक वर्षों से कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। इसलिए, इस मामले ने माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम ही रहेगा, सरकार ने 10 किलोग्राम वजन की अफवाहों का खंडन किया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। केंद्र सरकार ने पिछले एक सप्ताह से देश भर में गैस सिलेंडरों को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि गैस सिलेंडर में केवल सामान्य मात्रा में गैस यानी 14.2 किलोग्राम ही होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस प्रकार, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि खाना पकाने के गैस सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम की जगह 10 किलोग्राम गैस भरी जाएगी। ऐसी खबरों के पीछे यह तर्क दिया गया था कि अगर सिलेंडर का वजन कम किया जाए तो अधिक लोगों को गैस की आपूर्ति की जा सकेगी। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सरकार से पूछा गया कि क्या वह गैस सिलेंडरों की क्षमता घटाकर 10 किलोग्राम करने पर विचार कर रही है, तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है। लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी खबरें भ्रामक और अफवाहें हैं।

बेस्ट राइटर का ऐवॉर्ड पाने वाले टीचर

(जीएनएस)। गुजरात स्टेट चिल्ड्रन्स लिटरेचर एकेडमी का सालाना कन्वेंशन 22 फरवरी 2026 को गुजरात विश्वकोष भवन में हुआ। इसमें साल 2023-2024 में पब्लिश हुई चिल्ड्रन्स लिटरेचर की किताबों में से बेस्ट किताबें चुनी गईं और उनके लेखकों को अवॉर्ड दिया गया। जिसमें, मॉडर्न चिल्ड्रन्स राइटर के तौर पर मशहूर श्री निकेताबेन व्यास को उनकी कॉमिक चिल्ड्रन्स स्टोरी बुक 'गंगुना पराक्रमो' के लिए शील्ड और कैश प्राइज के साथ कुसुमबेन भूपेंद्रभाई दवे बेस्ट राइटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। गुजरात स्टेट टेक्स्टबुक बोर्ड और समग्र शिक्षा अभियान के साथ राइटर और रिव्यूअर के तौर पर काम करने वाली श्री निकेताबेन व्यास ने अपने यूनिक तरीके से चिल्ड्रन्स लिटरेचर को एजुकेशनल किताबें - गुजराती सीखो पार्ट 1, गुजराती सीखो पार्ट 2, चित्रवर्ता सीरीज पार्ट 1 से 10, सचित्र प्रज्ञा रीडिंग

सीरीज - दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने गंगू का पराक्रम (बच्चों की हास्य कहानियाँ), चीकू और सात जादूगरनी (टीनएज एडवेंचर स्टोरी), सुगंधवाली अँगूठी (बच्चों की कहानियाँ), बिल्ली नो फोटो छपायों खोटो (बच्चों की कहानी), बकाना गतकडा (हास्य व्यंग्य कहानियाँ), नेशनल हाईवे (सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल) जैसी किताबों के ज़रिए मातृभाषा के प्रचार-प्रसार में अनोखा योगदान दिया है। उनकी रचनाएँ कई बच्चों की मैगज़ीन जैसे फुलवाड़ी, बाल सृष्टि, बाल दुनिया, बाल भास्कर, जगमग वगैरह में रेगुलर छपती रहती हैं।

श्री निकेताबेन व्यास, जिन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए 5 जनवरी 2026 को गुजरात राज्य की माननीय शिक्षामंत्री श्रीमती रीवाबा जडेजा ने साहित्य साधना अवॉर्ड से सम्मानित किया है, अभी एलिसब्रिज स्कूल नंबर 30, स्कुलबोर्ड अहमदाबाद में टीचर के तौर पर काम कर रही हैं।

क्रूड ऑयल वायदा में 289 रुपये की वृद्धिः सोना वायदा 426 रुपये बढ़ा, चांदी वायदा में 1026 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 567764.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 46522.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 521238.47 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 34465 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4579.18 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 37155.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 138411 रुपये के भाव पर खूलकर, 140800 रुपये के दिन के उच्च और 136292 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139260 रुपये के पिछले बंद के सामने 426 रुपये या 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 139686 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 74 रुपये या 0.06 फीसदी औंधकर 113994 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 20 रुपये या 0.14 फीसदी औंधकर 14283 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 137990 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140880 रुपये और नीचे में 136312 रुपये पर पहुंचकर, 250 रुपये या 0.18 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139733 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 136256 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140900 रुपये और नीचे में 136256 रुपये पर पहुंचकर, 139750 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 0 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 139755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 218628 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 227470 रुपये और नीचे में 213562 रुपये पर पहुंचकर, 225167 रुपये के पिछले बंद के सामने 1026 रुपये या 0.46 फीसदी गिरकर 224141 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1404 रुपये या 0.61 फीसदी घटकर 228686 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1594 रुपये

या 0.69 फीसदी गिरकर 228700 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 3086.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 5.4 रुपये या 0.48 फीसदी गिरकर 1115.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 5 पैसे या 0.02 फीसदी की नरमी के साथ 310.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 35 पैसे या 0.11 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 331.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी की नरमी के साथ 187.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 46522.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 521238.47 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 37155.62 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34465 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5948.35 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8600 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8709 रुपये और नीचे में 8403 रुपये पर पहुंचकर, 289 रुपये या 3.46 फीसदी बढ़कर 8634 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 287 रुपये या 3.44 फीसदी की मजबूती के साथ 8637 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 274.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 277.7 रुपये के दिन के उच्च और 272.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 272.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.8 रुपये या 1.03 फीसदी की मजबूती के साथ 275.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 2.8 रुपये या 1.03 फीसदी की तेजी के संग 275.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 1015 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.1 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 996.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 24860.69 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 12294.92 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2653.12 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 218.25 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 12.68 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 194.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4368.81 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1563.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 8.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 2.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9016 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 58349 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 29257 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 370504 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64993 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7203 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19388 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75186 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16797 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 24769 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 33754 पॉइंट पर खूलकर, 34465 के उच्च और 33754 के नीचले स्तर को छूकर, 148 पॉइंट बढ़कर 34465 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 8500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 150.2 रुपये की बढ़त के साथ 918.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 275 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 3.05 रुपये हुआ।

सोना मार्च 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 496.5 रुपये की गिरावट के साथ 75.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 391.5 रुपये की गिरावट के साथ 685.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.05 रुपये की गिरावट के साथ 17.24 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 59.2 रुपये की गिरावट के साथ 212.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.95 रुपये की गिरावट के साथ 1.2 रुपये हुआ।

सोना मार्च 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 399.5 रुपये की गिरावट के साथ 154.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 263.5 रुपये की बढ़त के साथ 1333 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.59 रुपये की बढ़त के साथ 29.15 रुपये हुआ।